mental degradation in the affected areas due to pollution.

(c) Government have issued guidelines to take various measures to contain this disease like :

(i) Treatment of the affected manageable water areas with lime and salt ;

(ii) Treatment of affected fish with potassium permagnate ; and

(iii) To maintain hygenic conditions in open waters.

Agricultural Colleges/Agricultural Schools

592. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to start new agricultural colleges and schools during 8th Plan period ;

(b) if so, the target set for the entire country and Maharashtra respectively ; and

(c) by when these educational institutions are likely to start ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) No, Sir.

(b) and (c) The question does not arise.

Agricultural Research

593. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the plan outlay for the expenditure in the Eighth Five Year Plan on agricultural research, education and extension;

(b) the number of Krishi Vigyan Kendras proposed to be started in Eighth Plan period ; and

(c) by when they are likely to be started ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Sir. the outlay for the Department of Agricultural Research and Education for the year 1992-93 is Rs. 200 crores. The outlay for the eighth Five Year Plan has not been decided.

(b) The number will depend upon the outlay for Eighth Five Year Plan.

(c) Does not arise.

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

594. श्री लक्खीराम अग्रवाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वियन कर रही है और यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार ने मध्य प्रदेश की उन्नत किस्म के तिलहन बीजों की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) उन्नत किस्म के तिलहन बीज के वितरण के संबंध में सरकार की नीति क्या है और सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत बीजों, पौध रक्षण उपायों, जैव-उर्वरकों, जिप्सम पाइराइट्स, उन्नत कृषि उपकरणों तथा प्रदर्शनों के लिए सहायता दी गई है। भारत सरकार द्वारा 1991–92 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए उक्त घटकों हेतु स्वीकृत सहायता लगभग 531.90 लाख रुपये हैं।

(ख) तिलहनों के अन्तर्गत, 1991–92 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को मुख्यतया सोयाबीन, मूंगफली, तथा तोरिया सरसों की उन्नत किस्मों के करीब 449 क्विंटल प्रजनक बीज तथा 99,585 क्विंटल प्रमाणित बीज सप्लाई किए गये। बीजों की सप्लाई का प्रबन्ध भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि विश्वविद्यालयों, मध्य प्रदेश बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) बड़ी संख्या में किसानों में बीजों के वितरण को बढ़ावा देने हेतु बीज मिनिकिटों के वितरण तथा राजसहायता

प्राप्त दरों पर प्रमाणित क्वालिटी के बीजों की सप्लाई का एक कार्यक्रम तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किया गया है। बीज ग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का एक घटक है, भी उन्नत बीज उत्पादन का आयोजन किया जाता है।

मध्य प्रदेश में सूखा

595. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बहुत से इलाके सूखाग्रस्त हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा कोष से दी गई सहायता के अलावा कितनी सहायता राशि दी है ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त धनराशि दिये जाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं और अतिरिक्त धनराशि कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार राज्य के 26 जिलों में 78 तहसील, सूखे से प्रभावित हुई है, जिसके अंतर्गत 25.00 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र आता है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने आपदा राहत कोष के अलावा कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राज्य को नहीं दी है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय करने के लिए 220.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(घ) क्षति की सीमा और सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अपेक्षित केन्द्रीय सहायता का आकलन करने के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश को एक केन्द्रीय दल भेजने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् आगे की कार्यवाही की जाएगी।

मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र और गुजरात में सूखा

595. **कु० आत्रिया** :

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन राज्यों ने इस स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सूखे की मात्रा निम्न प्रकार बतायी गई है :—

(i) मध्य प्रदेश :

(1)	जिलों की संख्या	26 (आंशिक रूप से)
(2)	प्रभावित जन-संख्या	107.75 लाख